भारत संघ

बनाम

थमिशारसी और अन्य

1 मई, 1995

[जे. एस. वर्मा और श्रीमती सुजाता वी. मनोहर, न्यायाधिपतिगण]

नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985-धारा 37-जमानत-90 दिनों की अवधि के भीतर शिकायत दर्ज करने में चूक-जमानत पर रिहा होने का दावा-दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 की उप-धारा (2) का परंतुक लागू होना।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-धारा 167 (2), प्रोविसो की प्रयोज्यता- जमानत की -नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत अपराध -90 दिनों की अवधि के भीतर शिकायत दर्ज करने में चूक-जमानत पर रिहा होने का दावा-उप-धारा के लिए परंतुक धारा 167 की उपधारा (2)की प्रयोज्यता।

एक सूचना के आधार पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मद्रास से इज़राइल को निर्यात किए गए फ्लास्क की एक खेप जब्त की, जिसमें हशीश उसमें छिपा हुआ था। मद्रास में अभियुक्तों के परिसरों की तलाशी ली गई और संबंधित अधिकारियों द्वारा उनके बयान दर्ज किए गए। इन अभियुक्तों को **27-6-1994** पर गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्त के खिलाफ शिकायत धारा **167 Cr.P.C** की उप-धारा **(2)** के परंतुक में निर्दिष्ट गिरफ्तारी के अधिकतम **90** दिनों की अवधि के भीतर दर्ज नहीं की गई थी,

क्योंकि कुल अवधि जिसके लिए अभियुक्त को जाँच के दौरान हिरासत में भेजा जा सकता है। अभियुक्तों ने **90** दिनों की निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर जमानत पर रिहा होने का दावा किया और उन्हें केवल उसी आधार पर जमानत पर रिहा होने का निर्देश दिया गया था। उच्च न्यायालय ने जमानत को रद्द करने के अनुरोध को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उप-धारा **(2) 167 Cr.P.C** के परंतुक को उस अवधि के भीतर शिकायत दर्ज नहीं करने की चूक में नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट**, 1985** के तहत अपराध करने के लिए गिरफ्तार किए गए आरोपी द्वारा लागू किया जा सकता है। इसलिए विशेष अनुमति द्वारा ये अपीलें पेश हैं।

भारत संघ की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि एन**.** डी**.** पी**.** एस**.** अधिनियम और विशेष रूप से धारा **36** और **37** में विशेष प्रावधानों के आधार पर**,** इसके तहत धारा **167 Cr.P.C** की उप-धारा **(2)** में परंतुक के आवेदन को किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को एन**.** डी**.** पी**.** एस**.** अधिनियम के तहत दंडनीय मामले में बाहर रखा गया था।

प्रत्यर्थिगण ने तर्क दिया कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम की योजना दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 की उप-धारा (2) पर ऐसे मामलों में इसके अपवर्जन का संकेत देने के बजाय परंतुक के लागू होने का समर्थन किया।

विचार के लिए उठाया गया प्रश्न यह था कि क्या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 167 की उप धारा (2) के प्रावधान को अपराध करने के लिए गिरफ्तार किए गए

अधिनियम, 1985, के आरोपी द्वारा लागू किया जा सकता है। यदि उस अवधि के भीतर शिकायत दायर नहीं की जाती है, तो उसमें निर्दिष्ट कुल अवधि की समाप्ति पर जमानत पर रिहाई का दावा करने के लिए।

इन अपीलों को खारिज करते हुए, न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया:

1.1 . नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम**, 1985** की धारा **37** की उप**-**धारा **(1)** के खंड **(**बी**)** में निर्दिष्ट जमानत देने की सीमा केवल तभी आती है जब गुण**-**दोष के आधार पर जमानत देने का सवाल उठता है। अपनी प्रकृति से प्रावधान तब आकर्षित नहीं होता है जब आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा **167** की उप**-**धारा **(2)** के आधार पर जांच के दौरान अनुमत हिरासत की अधिकतम अवधि के भीतर शिकायत दर्ज करने में चूक के कारण जमानत की मंजूरी स्वचालित होती है। धारा **167** की उप**-**धारा **(2)** के लिए परंतुक को आकर्षित करने के लिए एकमात्र तथ्य सामग्री जांच के दौरान अभिरक्षा की अनुमति देने के लिए उसमें निर्दिष्ट अधिकतम अवधि के भीतर शिकायत दर्ज करने में चूक है न कि मामले के गुण**-**दोष जो शिकायत दर्ज होने तक अदालत के समक्ष अभियुक्त के अपराध के बारे में विश्वास बनाने के लिए उचित आधारों के अस्तित्व को निर्धारित करने के लिए नहीं हैं।

1.2 . धारा **36-**ए की उप**-**धारा **(3)** में प्रावधान है कि आपराधिक संहिता की धारा **439** के तहत जमानत के संबंध में उच्च न्यायालय की विशेष शक्तियां एन**.** डी**.** पी**.** एस**.** अधिनियम की धारा **36-**ए में निहित किसी भी चीज़ से प्रक्रिया

प्रभावित नहीं होगी। अधिनियम, धारा **167** की उप-धारा **(2)** अधिनियम की धारा **36-**ए द्वारा स्पष्ट रूप से लागू की गई है और अधिनियम की योजना यह है कि संहिता के प्रावधान लागू होंगे, सिवाय इसके कि इस अधिनियम के तहत की गई गिरफ्तारी के संबंध में इस अधिनियम में कोई असंगत प्रावधान है। जिस संदर्भ में धारा **37 (1) (**बी**)** का अर्थ लगाया जाना है जिसमें जमानत देने की सीमाएँ निर्दिष्ट की गई हैं। दंड प्रक्रिया संहिता धारा के संबंधित प्रावधान **437** है न कि धारा **167** जिसे असंगत माना जा सकता है।

1.3 . दंड प्रक्रिया संहिता की धारा **437** में जमानत पर रिहा करने की शक्ति पर सीमा उस शक्ति पर प्रतिबंध की प्रकृति में है यदि इस विश्वास के लिए उचित आधार मौजूद हैं कि अभियुक्त दोषी है। एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा **37** में इस शक्ति पर सीमा उस शक्ति के प्रयोग के लिए, एक पूर्ववर्ती शर्त की प्रकृति में है ताकि अभियुक्त को जमानत पर तब तक रिहा ना किया जाए जब तक कि अदालत को यह विश्वास न हो कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि वह दोषी नहीं है। दंड संहिता की धारा **437** के तहत, जमानत देने की शक्ति पर प्रतिबंध को आकर्षित करने के लिए अभियुक्त के अपराध में विश्वास का समर्थन करने के लिए उचित आधारों का अस्तित्व दिखाना अभियोजन पक्ष का काम है; लेकिन धारा **37** एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत, अभियुक्त को यह करना चाहिए कि आधारों का अस्तित्व दिखाएँ विश्वास दिलाने के लिए कि वह दोषी नहीं है, पूर्ववर्ती शर्त को संतुष्ट करने के लिए और जमानत देने की शक्ति पर प्रतिबंध हटा देने के लिए। धारा **37** में प्रावधान इस हद तक

कि यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा **437** के साथ असंगत है, संहिता में संबंधित प्रावधानों को हटा देता है और दंड प्रक्रिया संहिता के तहत सीमाओं के अलावा जमानत देने पर सीमाएं लगाता है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा **437** के तहत सीमाएं और केवल इस उद्देश्य के लिए अधिनियमित की गई थीं; और उनका प्रभाव दंड प्रक्रिया संहिता की धारा **167** की उप-धारा **(2)** पर परंतुक की प्रयोज्यता को बाहर करने का नहीं है। जो जाँच के दौरान अभियुक्त की अभिरक्षा की कुल अनुज्ञेय अवधि से संबंधित एक अलग क्षेत्र में कार्य करता है। धारा **167 Cr.P.C** की उप-धारा **(2)** में परंतुक की प्रयोज्यता को बहिष्कृत करने के लिए, ऐसे मामलों में विपरीत इरादे का संकेत देने वाले एक स्पष्ट प्रावधान की आवश्यकता थी या कम से कम कोई प्रावधान जिनमें से इस तरह का निष्कर्ष आवश्यक निहितार्थ से निकला था। एन. डी. पी. एस. अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और अधिनियम की योजना इंगित करती है कि जाँच के दौरान अभियुक्त की अभिरक्षा की कुल अवधि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा **167** में पाई जाती है, जो स्पष्ट रूप से लागू होती है। इस अधिनियम में असंगत किसी भी प्रावधान का अभाव महत्वपूर्ण है।

नटबर परिदा बिष्णु चरण परिदा बटकृष्ण परिदा बालाजी परिदा बनाम उड़ीसा राज्य, [1975] तितंबा एस. सी. आर. 137, पर आधार लिया गया।

मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो बनाम किशन लाल गुप्ता, [1991] 1 एस. सी. सी. 705, विशिष्ट।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार : आपराधिक अपील सं. **611-612/ 1995**

मद्रास उच्च न्यायालय के एच. सी. पी. सं. 1675 और 1692/1991 के 14.12.94 दिनांकित निर्णय और आदेश से।

अपीलार्थी के लिए के. टी. एस. तुलसी, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, वी. जे. फ्रांसिस और वी. के. वर्मा।

प्रत्यर्थिगण के लिए राम जेठमलानी, बी. कुमार और के. के. मणि।

न्यायालय का निर्णय निम्न के द्वारा दिया गया था

जे. एस. वर्मा, जे.

विशेष अनुमति याचिकाओं को अनुमति दी गई।

निर्णय के लिए कानून का आम सवाल हैः क्या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 167 की उप-धारा (2) का परंतुक को नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम, 1985 (जिसे इसके बाद "एन. डी. पी. एस. अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) के तहत अपराध करने के लिए गिरफ्तार किए गए अभियुक्त द्वारा लागू किया जा सकता है, कुल अवधि की समाप्ति, जो उसमें निर्दिष्ट है, पर जमानत पर रिहाई का दावा कर सकते हैं यदि उस अवधि के भीतर शिकायत दायर नहीं की जाती है ? मद्रास उच्च न्यायालय ने इस प्रश्न का उत्तर सकारात्मक रूप से दिया है और उन उत्तरदाताओं को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है जिन्हें एन. डी. पी. एस.

अधिनियम के तहत अपराध करने के लिए गिरफ्तार किया गया था तथा उस अवधि के भीतर उनके विरूदध शिकायत दर्ज करने में विफल रहने पर । इसलिए विशेष अनुमति द्वारा ये अपीलें पेश हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य कुछ ही हैं। ऐसा माना गया है कि, मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो को एक गुप्त सूचना मिली-कि मद्रास से इज़राइल को निर्यात किए गए फ्लास्क की एक खेप में हशीश छिपा हुआ था; और इस गुप्त सूचना के अनुसरण में खेंप को इज़राइल में 8.6.1994 पर जब्त कर लिया गया था। सूचना के आधार पर आरोपी अरमुखम, नागराज और आरिफ यू. पटेल के परिसरों की मद्रास में तलाशी ली गई और संबंधित प्राधिकारीयों द्वारा उनके बयान दर्ज किए गए। इन आरोपियों को 27.6.1994 को गिरफ्तार किया गया और मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया जिन्होंने समय-समय पर रिमांड मंजूर की। हमें मादक द्रव्यों साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम, 1988 के अवैध व्यापार की रोकथाम के तहत आरोपियों की निवारक निरोध के आदेशों से संबंधित तथ्यों का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, चूंकि यह एक अलग कार्यवाही का विषय है जिसमें निवारक निरोध के आदेश को चुनौती दी गई थी। माना गया है, कि धारा 167 सीआर की एच उपधारा (2) के परंतुक में निर्दिष्ट गिरफ्तारी के 90 दिनों की अधिकतम अवधि के भीतर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं की गई थी। क्यूँकि कुल अवधि जिसके लिए जाँच के दौरान अभियुक्त को हिरासत में लिया जा सकता है। तदनुसार, अभियुक्त ने 90 दिनों की निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर जमानत पर रिहा होने का दावा किया और उन्हें केवल उसी आधार पर ज़मानत पर रिहा करने का

निर्देश दिया गया है। उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश द्वारा जमानत रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया है। इसलिए, निर्णय के लिए ये अपीलें पेश की गयी हैं जिसमें कानून का उपरोक्त सामान्य प्रश्न शामिल है।

इस बीच, यह उल्लेख किया जा सकता है कि उपरोक्त निर्धारित अवधि के बाद में, शिकायत दायर की गई है, लेकिन यह बाद का तथ्य कानून के उपरोक्त प्रश्न के निर्णय के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। यह सामान्य आधार है कि जमानत देने वाले विवादित आदेश की वैधता का फैसला शिकायत दर्ज करने से पहले उसकी तारीख के संदर्भ में किया जाना है। गुण-दोष के आधार पर अब उपलब्ध सामग्री या निवारक निरोध के लिए अभियुक्त के दायित्व के आधार पर अभियुक्त को हिरासत में लेने की शक्ति एक अलग प्रश्न है जो यहां विचारणीय नहीं है, और निर्णय के एकमात्र प्रश्न पर इन अपीलों में लिए गए दृष्टिकोण से अप्रभावित रहेगा।

विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का निवेदन है कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम में विशेष प्रावधानों के आधार पर और विशेष रूप से उसकी धारा 36 और 37, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 की उप-धारा (2) पर परंतुक की प्रयोज्यता को एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत दंडनीय किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति के मामले में बाहर रखा गया है। दूसरी ओर, प्रत्यर्थिगण के विद्वान अधिवक्ता श्री राम जेठमलानी का तर्क है कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम की योजना दंड प्रक्रिया संहिता

की धारा 167 की धारा (2)में उपखंड पर परंतुक की इसके बहिष्करण का संकेत देने के बजाय,प्रयोज्यता का समर्थन करती है।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में प्रासंगिक प्रावधान निम्नानुसार हैं:

"4. भारतीय दण्ड संहिता और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचारण- (1) भारतीय दण्ड संहिता 1860 (1860 का 45) के अधीन सब अपराधों का अन्वेषण, जांच, विचारण और उनके सम्बन्ध में अन्य कार्यवाही इसमें इसके पश्चात् अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार की जाएंगी।

(2) किसी अन्य विधि के अधीन सब अपराधों का अन्वेषण, जांच, विचारण और उनके सम्बन्ध में अन्य कार्यवाही इन्हीं उपबन्धों के अनुसार किन्तु ऐसे अपराधों के अन्वेषण, जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही की रीति या स्थान का विनियमन करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति के अधीन रहते हुए की जाएगी।

167. जब चौबीस घण्टे के अन्दर अन्वेषण पूरा न किया जा सके तब प्रक्रिया -

(1) जब कभी कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में निरुद्ध है और यह प्रतीत हो कि अन्वेषण धारा 57 द्वारा नियत चौबीस घण्टे की अवधि के अन्दर पूरा नहीं किया जा सकता और यह विश्वास करने के लिए आधार है कि अभियोग या इत्तिला दृढ़ आधार पर है तब पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी या यदि अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी उपनिरीक्षक से निम्नतर पंक्ति का नहीं है तो वह, निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट को इसमें इसके पश्चात् विहित डायरी की मामले से

सम्बन्धित प्रविष्टियों की एक प्रतिलिपि भेजेगा और साथ ही अभियुक्त व्यक्ति को भी उस मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा।

(2) वह मजिस्ट्रेट, जिसके पास अभियुक्त व्यक्ति इस धारा के अधीन भेजा जाता है, चाहे उस मामले के विचारण की उसे अधिकारिता हो या न हो, अभियुक्त का ऐसी अभिरक्षा में, जैसी वह मजिस्ट्रेट ठीक समझे इतनी अवधि के लिए, जो कुल मिलाकर पन्द्रह दिन से अधिक न होगी, निरुद्ध किया जाना समय-समय पर प्राधिकृत कर सकता है तथा यदि उसे मामले के विचारण की या विचारण के लिए सुपुर्द करने की अधिकारिता नहीं है और अधिक निरुद्ध रखना उसके विचार में अनावश्यक है तो वह अभियुक्त को ऐसे मजिस्ट्रेट के पास, जिसे ऐसी अधिकारिता है, भिजवाने के लिए आदेश दे सकता है।

परन्तु -

[(क) मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति का पुलिस अभिरक्षा से अन्यथा निरोध पन्द्रह दिन की अवधि से आगे के लिए उस दशा में प्राधिकृत कर सकता है जिसमें उसका समाधान हो जाता है कि ऐसा करने के लिए पर्याप्त आधार है, किन्तु कोई भी मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति का इस पैरा के अधीन अभिरक्षा में निरोध- (i) कुल मिलाकर नब्बे दिन से अधिक की अवधि के लिए प्राधिकृत नहीं करेगा जहां अन्वेषण ऐसे अपराध के सम्बन्ध में है जो मृत्यु, आजीवन कारावास या दस वर्ष से अन्यून की अवधि के लिए कारावास से दण्डनीय है; (ii) कुल मिलाकर साठ दिन से अधिक की अवधि के लिए

प्राधिकृत नहीं करेगा जहां अन्वेषण किसी अन्य अपराध के सम्बन्ध में है, और, यथास्थिति, नब्बे दिन या साठ दिन की उक्त अवधि की समाप्ति पर यदि अभियुक्त व्यक्ति जमानत देने के लिए तैयार है और दे देता है तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा और यह समझा जाएगा कि इस उपधारा के अधीन जमानत पर छोड़ा गया प्रत्येक व्यक्ति अध्याय 33 के प्रयोजनों के लिए उस अध्याय के उपबन्धों के अधीन छोड़ा गया है;]

[(ख) कोई मजिस्ट्रेट इस धारा के अधीन किसी अभियुक्त का पुलिस अभिरक्षा में निरोध तब तक प्राधिकृत नहीं करेगा जब तक कि अभियुक्त उसके समक्ष पहली बार और तत्पश्चात् हर बार, जब तक कि अभियुक्त पुलिस की अभिरक्षा में रहता है, व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं किया जाता है किंतु मजिस्ट्रेट अभियुक्त के या तो व्यक्तिगत रूप से या इलैक्ट्रानिक दृश्य संपर्क माध्यम से पेश किए जाने पर न्यायिक हिरासत में निरोध को और बढ़ा सकेगा।]

(ग) कोई द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट, जो उच्च न्यायालय द्वारा इस निमित्त विशेषतया सशक्त नहीं किया गया है, पुलिस की अभिरक्षा में निरोध प्राधिकृत न करेगा।

[स्पष्टीकरण 1- -शंकाएं दूर करने के लिए इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि पैरा (क) में विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त हो जाने पर भी अभियुक्त व्यक्ति तब तक अभिरक्षा में निरुद्ध रखा जाएगा जब तक कि वह जमानत नहीं दे देता है।]

xxxxxxxxxx. xxxxxx. xxxxx

36 क. (1) विशेष न्यायालयों द्वारा विचारणीय ड अपराध-दंड प्रक्रिया सहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी,

(क) इस अधिनियम के अधीन ऐसे सभी अपराध, जो तीन वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय है, उस क्षेत्र के लिए, जिसमें अपराध किया गया है, गठित. विशेष न्यायालय द्वारा हो या जहां ऐसे क्षेत्र के लिए एक से अधिक विशेष न्यायालय है वहां, उनमें से ऐसे एक के द्वारा ही, जिसे सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, विचारणीय होंगे ।

(ख) जहां इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के अभियुक्त या उसके किए जाने के संदेहयुक्त किसी व्यक्ति को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 167 की उपधारा (2) या उपधारा (2 क) के अधीन किसी मजिस्ट्रेट को भेजा जाता है, वहां ऐसे मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को ऐसी अभिरक्षा में, जो वह उचित समझे, कुल मिलाकर पन्द्रह दिन से अनधिक की अवधि के लिए, जहां ऐसा मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट है और कुल मिलाकर सात दिन की अवधि के लिए, जहां ऐसा मजिस्टेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट है. निरोध के लिए प्राधिकृत कर सकेगा :

परन्तु ऐसे मामलों में, जो जहां ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय हैं,

(i) जब ऐसा व्यक्ति पूर्वोक्त रूप में उसको भेजा जाता है, या

(ii) उसके द्वारा प्राधिकृत निरोध की अवधि की समाप्ति पर या उसके पूर्व किसी भी समय, यह विचार है कि ऐसे व्यक्ति का निरोध अनावश्यक है, वहां वह ऐसे व्यक्ति को अधिकारिता रखने वाले विशेष न्यायालय को भेजे जाने का आदेश करेगा;

(ग) विशेष न्यायालय, खंड (ख) के अधीन उसको भेजे गए व्यक्ति के संबंध में, उसी शक्ति का प्रयोग कर सकेगा जिसका प्रयोग किसी मामले का विचारण करने की अधिकारिता रखने वाला मजिस्ट्रेट, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 167 के अधीन, ऐसे मामले में किसी अभियुक्त व्यक्ति के संबंध में, जिसे उस धारा के अधीन उसको भेजा गया है, कर सकता हैं;

xxxxx xxxxxx xxxxxx

(3) इस धारा की कोई बात दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 439 के अधीन जमानत से संबंधित उच्च न्यायालयकी विशेष शक्तियों को प्रभावित करने वाली नहीं समझी जाएगी और उच्च न्यायालय ऐसी शक्तियों का प्रयोग, जिसके अंतर्गत उस धारा की उप धारा (1) के खंड (ख) के अधीन शक्ति भी है, ऐसे कर सकेगा मानो उस धारा में "मजिस्ट्रेट" के प्रति निर्देश के अंतर्गत - धारा 36 के अधीन गठित "विशेष न्यायालय" के प्रति निर्देश भी हैं ।

36 - सी. विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों को संहिता का लागू होना- इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उपबंध (जिसके अंतर्गत जमानत और बंधपत्रों से संबंधित उपबंध भी

हैं किसी विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों को लागू होंगे और उक्त उपबंधों के प्रयोजनों के लिए विशेष न्यायालय, एक सेशन न्यायालय समझा जाएगा, और विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन संचालित करने वाला व्यक्ति लोक अभियोजक समझा जाएगा।

37. अपराधों का संज्ञेय और अजमानतीय होना— (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) किसी बात के होते हुए भी,

(क) इस अधिनियम के अधीन दंडनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा;

(ख) '[धारा 19 या धारा 24 या धारा 27क के अधीन अपराधों के लिए और वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित अपराधों के लिए भी दंडनीय किसी अपराध] के अभियुक्त किसी भी व्यक्ति को जमानत पर या मुचलके पर तभी निर्मुक्त किया जाएगा जब-

(i) लोक अभियोजक को ऐसी निर्मुक्ति के लिए किए गए आवेदन का विरोध करने का अवसर दे दिया गया है, और

(ii) जहां लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है वहां न्यायालय का यह समाधान हो गया हैं कि यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार है कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर होने के दौरान उसके द्वारा कोई अपराध किए जाने की संभावना नहीं हैं।

xxxxx xxxxxx xxxxxx

51. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रावधान वारंट, गिरफ्तारी, तलाशी और बरामदगी पर लागू होता है। - दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) के प्रावधान लागू होंगे, जहाँ तक वे इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं हैं, जारी किए गए सभी वारंटों और की गई गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती के लिए इस अधिनियम के तहत।"

धारा 36-ए यह स्पष्ट करती है कि एक व्यक्ति जिस पर एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अपराध करने का आरोप लगाया गया है या संदेह है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 की उप-धारा (2) या उप-धारा (2-ए) के तहत मजिस्ट्रेट को अग्रेषित किया जाना है और अधिनियम की धारा 36 के तहत गठित विशेष न्यायालय उस धारा के तहत उसे भेजे गए उस व्यक्ति के संबंध में उसी शक्ति का प्रयोग करता है जिसका उपयोग अधिकार क्षेत्र वाला मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के तहत कर सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के तहत मजिस्ट्रेट की शक्ति का स्पष्ट संदर्भ विशेष रूप से इसकी उप-धारा (2), एक संकेत है कि संहिता की धारा 167 की उप-धारा (2) का कोई भी हिस्सा ऐसे मामले में तब तक लागू नहीं होता है जब तक कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम में इसके विपरीत कोई विशिष्ट प्रावधान न हो। इस निष्कर्ष को एन. डी. पी. एस. अधिनियम के कुछ अन्य प्रावधानों द्वारा पुष्ट किया गया है। धारा 36-सी में कहा गया है कि "इस अधिनियम में अन्यथा प्रावधान किए जाने के अलावा, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के प्रावधान (जमानत और बांड के प्रावधानों सहित) एक विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाही पर लागू होंगे।" यह इस बात को भी इंगित करता है कि जमानत और बांड

से संबंधित दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान "इस अधिनियम में अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर" के तहत एन. डी. पी. एस. अधिनियम के अंतर्गत एक विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाही पर लागू होते हैं। धारा 51 में यह भी कहा गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973, जहाँ तक वे इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं हैं, जारी किए गए सभी वारंटों, गिरफ्तरियों, खोज और जब्तियों पर लागू होगी, एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 37 को छोड़ कर एन. डी. पी. एस. अधिनियम का कोई अन्य प्रावधान का आश्रय नहीं जिस पर तर्क दें कि एन. डी. पी. एस. में कोई असंगत प्रावधान हैं जिस से धारा 167 Cr.P.C की उप-धारा (2) के लिए केवल परंतुक की प्रयोज्यता को बाहर किया गया है, जब कि संहिता की धारा 167 की उप-धारा (2) एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 36-ए द्वारा स्पष्ट रूप से लागू करने के लिए है।

इसलिए सवाल यह है : क्या एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 37 इस प्रकार का असंगत प्रावधान है, जो केवल धारा 167 Cr.P.C की उप-धारा (2) के परंतुक की प्रयोज्यता को बहिष्कृत करता है जब की, धारा 167 की उप-धारा (2) को स्पष्ट रूप से एन. डी. पी. एस. अधिनियम द्वारा लागू किया गया है? धारा 37 की उप-धारा (1) की शुरुआत में गैर-अवरोधक खंड इंगित करता है कि खंड (ए) और (बी) में प्रावधान अधिनियम में निहित समानांतर प्रवधानों से असंगत हैं। खंड (ए) हम इस तर्क को मानने में असमर्थ हैं।

धारा 37 की उप-धारा (1) के खंड (बी) में निर्दिष्ट जमानत देने की सीमाएँ केवल तभी आती हैं जब गुण-दोष के आधार पर जमानत देने का प्रश्न उत्पन्न होता है। अपनी प्रकृति से मात्र से प्रावधान तब आकर्षित नहीं होता है जब धारा 167 सी. आर.पी. सी. की उप-धारा (2) के आधार पर जांच के दौरान अनुमत हिरासत की अधिकतम अवधि के भीतर शिकायत दर्ज करने में चूक के कारण जमानत की मंजूरी स्वचालित होती है। धारा 167 की उप-धारा (2) के लिए परंतुक को आकर्षित करने के लिए एकमात्र तथ्य सामग्री जांच के दौरान अभिरक्षा की अनुमति देने के लिए उसमें निर्दिष्ट अधिकतम अवधि के भीतर शिकायत दर्ज करने में चूक है न कि मामले के गुण-दोष जो शिकायत के दाखिल होने तक है, शिकायत के अस्तित्व को निर्धारित करने के लिए, अभियुक्त के अपराध के बारे में विश्वास बनाने के लिए उचित आधारअदालत के समक्ष नहीं हैं । विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने तर्क दिया कि आरोप पत्र दायर होने से पहले ही केस डायरी की सामग्री के संदर्भ में जांच के दौरान यह विश्वास हो सकता है। ये गलत है। शिकायत दर्ज की जाती है तब तक कि अभियुक्त को ऐसी कोई सामग्री प्रदान नहीं की जाती है जिससे वह एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 37 (1) (b) द्वारा उस पर लगाए गए बोझ का निर्वहन कर सके। हमारी राय में, धारा 37 की उप-धारा (1) के खंड (बी) का ऐसा निर्माण अनुज्ञेय नहीं है।

धारा 36-ए की उप-धारा (3) में प्रावधान है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत जमानत के संबंध में उच्च न्यायालय की धारा 36-ए एन. डी. पी. एस. अधिनियम में निहित किसी भी चीज़ से प्रभावित नहीं होगा। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 की

उप-धारा (2) को अधिनियम की धारा 36-ए द्वारा स्पष्ट रूप से संहिता के प्रावधान लागू होंगे सिवाय इसके कि इस अधिनियम के तहत की गई गिरफ्तारी के संबंध में इस अधिनियम में कोई असंगत प्रावधान है। यही वह संदर्भ है जिसमें धारा 37 (1) (बी) का अर्थ लगाया जाना चाहिए जिसमें जमानत देने की सीमाओं को निर्दिष्ट किया गया है। इसलिए, हमें दंड प्रक्रिया संहिता में अधिनियम की धारा 37 (1) (बी) समानांतर प्रावधानों पर ध्यान देना चाहिए जिन को असंगत माना जा सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता में, यह धारा 437 है न कि धारा 167 जो इस उद्देश्य के लिए संबंधित प्रावधान है। गैर-जमानती अपराध के मामले में धारा 437 के तहत जमानत के अनुदान में संबंधित सीमा इस प्रकार हैः

> "(i) ऐसे व्यक्ति को ज़मानत पर नहीं छोड़ा जाएगा यदि ऐसा प्रतीत होता है की यह विश्वास करने के लिए उचित आधार कि वह एक मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दोषी रहा है।"

दूसरे शब्दों में, संहिता की धारा 437 के तहत व्यक्ति को जमानत पर रिहा नहीं किया जाना है जब कि, "यदि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार दिखाई देते हैं कि वह किसी अपराध का दोषी है… ."। एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 37 के तहत, अभियुक्त को तब तक जमानत पर रिहा नहीं किया जाएगा जब तक कि "अदालत का समाधान नहीं हो जाता है कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि वह इस तरह के अपराध का दोषी नहीं है।" जमानत से इनकार करने के लिए

अभियुक्त के अपराध में विश्वास करने के लिए उचित आधारों की आवश्यकता अधिक कठोर है और इसलिए, अभियुक्त के लिए इस विश्वास के लिए उचित आधारों की आवश्यकता से अधिक फायदेमंद है कि वह एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 37 के तहत अपराध का दोषी नहीं है। दंड संहिता की धारा 437 के तहत भार अभियोजन पक्ष पर है यह विश्वास करने के लिए कि अभियुक्त दोषी है, उचित आधारों का अस्तित्व दिखाने के लिए जबकि अधिनियम की धारा 37 के तहत इस विश्वास के लिए उचित आधारों का अस्तित्व दिखाने का भार अभियुक्त पर है कि वह अपराध का दोषी नहीं है। पहले मामले में, के पक्ष में निर्दोषता की धारणा अभियुक्त को केवल अभियोजन पक्ष द्वारा यह विश्वास करने के लिए उचित आधारों का अस्तित्व दिखाने पर विस्थापित किया जाता है कि अभियुक्त दोषी है जबकि एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अभियुक्त को यह दिखाना होता है कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि वह दोषी नहीं है।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 में जमानत पर रिहा करने की शक्ति पर सीमा, उस शक्ति पर प्रतिबंध की प्रकृति में है, यदि इस विश्वास के लिए उचित आधार मौजूद हैं कि अभियुक्त दोषी है। दूसरी ओर, एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 37 में इस शक्ति पर सीमा उस शक्ति के प्रयोग के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त की प्रकृति में है, ताकि, अभियुक्त जमानत पर तब तक रिहा नहीं किया जाएगा जब तक कि न्यायालय का निश्चित नहीं हो जाता है कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि वह दोषी नहीं है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 के तहत, जमानत देने की शक्ति पर प्रतिबंध

को आकर्षित करने के लिए अभियुक्त के अपराध में विश्वास का समर्थन करने के लिए उचित आधारों का अस्तित्व दिखाना अभियोजन पक्ष का काम है; लेकिन धारा 37 एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत, अभियुक्त पर निर्दोष होने का आधार दिखने का भार है, जिसे पूर्ववर्ती शर्त को पूरा करने और जमानत देने की शक्ति पर प्रतिबंध हटाने के लिए इस विश्वास के लिए आधारों का अस्तित्व दिखाना होगा कि वह दोषी नहीं है। यह दोनों प्रावधानों के बीच का अंतर प्रतीत होता है जो एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 37 को और अधिक कठोर बनाता है।

तदनुसार, धारा 37 में प्रावधान इस हद तक है कि यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 के साथ असंगत है, संहिता में प्रावधानों और धारा 37 की उप-धारा (2) में स्पष्ट रूप से प्रदान की गई दंड प्रक्रिया संहिता के तहत सीमाओं के अलावा जमानत देने पर सीमाएं लगाना धारा 37 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट जमानत देने की ये सीमाएँ इसके अतिरिक्त हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 के तहत सीमाओं के लिए और केवल इस उद्देश्य के लिए अधिनियमित किया गया था; और उनके पास धारा 167 Cr.P.C की उप-धारा (2) के लिए परंतुक की प्रयोज्यता को बाहर करने का प्रभाव नहीं है जो जांच के दौरान अभियुक्त की अभिरक्षा की कुल अवधि से संबंधित एक अलग क्षेत्र में काम करता है।

हमारी राय में, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 की उप-धारा (2) पर परंतुक के प्रयोज्यता को बहिष्कृत करने के लिए, ऐसे मामलों में विपरीत इरादे का संकेत देने

वाले एक स्पष्ट प्रावधान की आवश्यकता थी या कम से कम कुछ प्रावधान अधिनियम इंगित करता है कि जाँच के दौरान अभियुक्त की अभिरक्षा की कुल अवधि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 में पाई जाती है। पी. सी. जो स्पष्ट रूप से लागू किया जाता है। इस अधिनियम में असंगत किसी भी प्रावधान का अभाव महत्वपूर्ण है।

आतंकवादी के प्रासंगिक प्रावधानों के साथ तुलना और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1987 (संक्षेप में "टाडा अधिनियम") उपयोगी है। धारा 20 में कुछ दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान के संशोधित अनुप्रयोग है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 20 की उप-धारा (4) उस संशोधन को निर्दिष्ट करता है जिसके साथ धारा 167 सी. आर. पी. सी. टाडा अधिनियम के तहत अपराध के आरोपी व्यक्ति पर लागू होता है। बदलाव में से एक जांच के दौरान अनुज्ञेय अभिरक्षा की लंबी कुल अवधि के लिए प्रावधान द्वारा इसमें स्पष्ट रूप से किया गया है। एक संबंधित प्रावधान एन. डी. पी. एस. अधिनियम में अनुपस्थित है। इसके बाद धारा 20 की उप-धारा (8) और (9) एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 37 की उप-धारा (1) और (2) के अनुरूप प्रावधान हैं। दोनों अधिनियमों के बीच यह समानता आश्चर्यजनक है और इस संदर्भ में टाडा अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (4) जैसे प्रावधान टाडा अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (4) के समान का अभाव अधिक महत्व रखता है और इसका समर्थन करता है। अधिनियम की धारा 37 में कुछ भी नहीं है, भले ही प्रावधान की टाडा अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (8) और (9) के साथ उल्लेखनीय समानता है। हमारी राय में, एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अपराध करने के लिए की गई

गिरफ्तारी के मामलों में धारा 167 Cr.P.C की उप धारा (2) पर परंतुक की प्रयोज्यता को बाहर नहीं करने का विधायी इरादा काफी स्पष्ट है।

यह तय है कि "न्यायालय के पास अभियुक्त की अभिरक्षा के लिए रिमांड की कोई शक्ति नहीं होगी जब तक कि कानून द्वारा शक्ति प्रदान नहीं की जाती है।" (नटबर परिदा बिष्णु चरण परिदा बटकृष्ण परिदा बाबाजी परिदा बनाम उड़ीसा राज्य, [1975] सप एससीआर 137)। इसलिए, शक्ति का पता क़ानून के कुछ प्रावधानों से लगाया जाना चाहिए। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 का स्पष्ट एन. डी. पी. एस. अधिनियम में इस शक्ति के प्रयोग के लिए उल्लेख है।आम तौर पर वहाँ जाँच के दौरान अनुज्ञेय रिमांड कुल अवधि के विनिर्देश द्वारा निर्धारित एक बाहरी सीमा भी होनी चाहिए । यह भी धारा 167 में प्रदान किया गया है। धारा 167 के केवल इस भाग को अपवर्जित करने के लिए, यह मानते हुए कि समय के संदर्भ में असीमित रिमांड की शक्ति प्रदान की जा सकती है, यह ही वस्तुतः विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का का तर्क है । धारा 167 Cr.P.C की उप-धारा (2) नटबर परिदा (ऊपर) में कहा गया था, इस प्रकारः

> "..... धाराओं के लिए परंतुक (ए) में निहित कानून धारा 167 (2) और नई संहिता की धारा 309 (2) इन शक्तियों को केवल पूर्व के तहत प्रदान करती है बाद के तहत नहीं - धारा 309 (2) तभी लागू होती है जब किसी अपराध का संज्ञान लिया गया हो और मुकदमा

आगे बढ़ाया गया हो। परंतु परंतुक (ए) में विधायिका का आदेश यह है कि आरोपी व्यक्ति को जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए यदि वह जमानत देने के लिए तैयार है और प्रस्तुत करता है और उसे 60 दिनों की अवधि से अधिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता है यदि जांच की जा सकती है। आपराधिक षड्यंत्र-हत्या, डकैती, अंतर-राज्यीय डकैती गिरोह या इस तरह के गंभीर अपराधों में, यह पुलिस के लिए संभव नहीं हो सकता है, परिस्थितियाँ जो हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में मौजूद हैं, के रहते 60 दिनों की अवधि के भीतर जांच पूरी करना। फिर भी विधायिका का इरादा ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायालय को कोई विवेकाधिकार नहीं दिया जाए और अभियुक्त को जमानत पर रिहा करना उसके लिए अनिवार्य बनाना। बेशक, परंतुक (ए) में यह प्रावधान किया गया है कि अभियुक्त धारा 167 के तहत जमानत पर रिहा किए जाने को इस तरह रिहा अध्याय XXXIII के प्रावधानों के तहत और के प्रयोजनों के लिए माना जाएगा । यह अदालत को उसे जमानत पर रिहा करने का अधिकार दे सकता है, यदि ऐसा करना आवश्यक समझता है, तो यह निर्देश देना कि ऐसा व्यक्ति गिरफ्तार किया गया और अध्याय XXXIII में आने वाली धारा 437 उप-धारा (5) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार हिरासत में लिया गया यह भी स्पष्ट है कि नई संहिता की धारा 309 के तहत संज्ञान लेने के बाद

रिमांड की शक्ति होनी चाहिए। लेकिन अगर 60 दिनों की अवधि के भीतर जांच पूरी करना संभव नहीं है । तो गंभीर और भयावह प्रकार के अपराधों में भी अभियुक्त जमानत पर रिहा किए जाने का हकदार होगा। इस तरह का कानून “अपराधी लोगों के लिए स्वर्ग” हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से ऐसा नहीं होगा, जैसा कि कभी-कभी होना, अदालतों के कारणमाना गया है। ऐसा विधानमंडल के आदेश के तहत होगा।" (जोर दिया गया)

विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बनाम किशन लाल और अन्य, [1991] 1 एस. सी. सी. 705 में इस न्यायालय का निर्णय पर मजबूत निर्भरता रखी । उस मामले में केवल एक ही बात तय की गई है कि उच्च न्यायालय की संहिता की धारा 439 के तहत जमानत देने की शक्ति आपराधिक प्रक्रिया एन. डी. पी. एस. अधिनियम की संशोधित धारा 37 में निहित सीमाओं के अधीन है क्योंकि वे अतिरिक्त सीमाएं जमानत देने के मामले में उच्च न्यायालय पर भी लागू होती हैं। यह एक अलग प्रश्न है। इसलिए वह निर्णय उस प्रश्न का उत्तर नहीं देता है जो वर्तमान मामले में विचार के लिए उत्पन्न होता है। एक अलग दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए हमारे समक्ष सुनवाई में दोनों पक्षों द्वारा इस न्यायालय के किसी अन्य निर्णय पर भरोसा नहीं किया गया है।

उपरोक्त कारणों से, इन अपीलों को खारिज कर दिया जाता है जिसके परिणामस्वरूप इसमें दिए गए अंतरिम आदेशों को हटाया जा रहा है। हालाँकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि यह निर्णय कानून के अनुसार किए गए किसी अन्य आदेश को प्रभावित नहीं करेगा जो प्रत्यर्थियों को हिरासत में रखने की अनुमति देने के लिए लागू हो सकता है।

याचिकाएं खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता अर्जिता सिंह द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।